

तस्करी की गतिविधियां छोड़ देने की शपथ

901. श्री मीठा लाल पटेल :

श्री के० मालप्पा:

श्री बी० एम० सुधीरन :

श्री निहार लास्कर :

क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख तस्करी ने सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण के सामने तस्करी गतिविधियां छोड़ देने की शपथ ली है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है, और नाम क्या हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) देश में तस्करी की गतिविधियों पर इसका सम्बन्ध रूप में क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख). जी. हां। सरकार को प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 30 अप्रैल, 1977 को बम्बई में 100 तस्करी ने श्री जयप्रकाश नारायण के समक्ष शपथ ली है कि वे तस्करी नहीं करेंगे और अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार की गतिविधियां जारी रखने से मना करेंगे और रोकेंगे और सरकार की मदद करेंगे। इस प्रकार के प्रमुख व्यक्तियों में हाजी मस्तान मिर्जा, युसुफ अब्दुल्ला पटेल, राजावली हिरजी मेघानी, इब्राहीम मच्छीवाला, डोंगरी का देवीचन्द, वर्धराज मुनिस्वामी, ललित ढोलकिया, बाबू बूधवाला, युसुफ मुपारीवाला, मजीद खान देशी (एहाद का) मैय्यद अहमद और सुकर नारायण बखिया शामिल हैं।

(ग) शपथ और सहयोग का प्रस्ताव, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सही दिशा में उठाये गये कदम हैं।

(घ) तस्करी पर इस शपथ का समग्र प्रभाव इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता। लेकिन, मामले की समीक्षा की जा रही है।

विभिन्न मंत्रालयों में मितव्ययिता लाने हेतु किये गये उपाय

902. श्री मीठा लाल पटेल : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में मितव्ययिता लाने हेतु किये गये उपायों के परिणामस्वरूप मंत्रालयों न अपने खर्च में कोई मितव्ययिता बरती है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). इस विषय का सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है। सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों से है। वित्त सचिव के 13-5-77 के अर्द्ध सरकारी पत्र और 27-5-77 के कार्यलय ज्ञापन की प्रतिलिपियां सभा पटल पर रखी गई हैं। [न्यालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 38(ए/77)] इन अनुदेशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं :-

मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी खर्च में किरायायत करने के लिए समीक्षा करें। यह समीक्षा उनके मौजूदा कार्यों, प्रणालियों और